मसालों का निर्यात बढ़ाने हेतु अनुरेखणीयता, संधारणीयता, जैव विविधता और प्रमाणन पर सहयोगात्मक परियोजनाएं

<u>क) राष्ट्रीय सतत मसाला कार्यक्रम</u>

स्पाइसेस बोर्ड, विश्व मसाला संगठन (डबल्यूएसओ), ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्स्पोर्टर्स फोरम (एआईएसईएफ़) तथा -आईडीएच (जो टिकाऊ व्यापार पहल का समर्थन करती है) और जीआईज़ेड, जर्मनी(जो जैवविविधता एवं व्यापार पर कार्य करती है) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग के साथ 'राष्ट्रीय सतत मसाला नेटवर्क कार्यक्रम (एनएसएसपी)' शीर्षक वाली परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुमार्गणीयता लाना और मसाला क्षेत्र में जैव विविधता के लिए उचित चिंता के साथ स्थिरता प्राप्त करना, निर्यात मांग वाले मसालों से संबंधित गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान करना और निर्यात और निर्यात वृद्धि को बनाए रखना है।

इस क्षेत्र से मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, शुरू में पांच मसालों, नामतः मिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, जीरा तथा छोटी इलायची और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित मसाले भी, की पहचान की गई है। मसालों के स्थायी उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के लिए सरकार, किसान समूह, कृषि क्षेत्र के साथ काम करने वाले एफपीओ, कृषि अनुसंधान संगठनों, प्रसंसकरणकर्ताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, विश्वविद्यालयों और वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पनधारियों के एक नेटवर्क को एक साथ लाया जा रहा है। यह आपूर्ति श्रृंखला में कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों का अभिसरण भी सुनिश्चित करेगा।

इस परियोजना/कार्यक्रम से संबंधित क्रियाकलापों केलिए डब्ल्यूएसओ, आईडीएच तथा जीआईज़ेड वित्तीय समर्थन प्रदान कर रहे हैं। स्पाइएस बोर्ड सकनीकी साझेदार है और अपने कार्यालय नेटवर्क के ज़रिए मसाला बढ़ानेवाले क्षेत्रों में कार्यक्रमों द्वारा अवधारित कार्यकलापों के समायोजन में अपना समर्थन देता है।

<u>ख) मसलों की ब्लॉक-चेन आधारित ट्रेसबिलिटी पर परियोजना</u>

यूएनडीपी की एक्सिलरेटर लैब, भारत, स्पाइसेस बोर्ड और जीएस1 के साथ संयुक्त रूप से "मसालों केलिए ब्लॉकचेन प्लैटफ़ार्म का विकास" परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के अधीन, ब्लॉकचेन तकनोलजी को इ-स्पाइस बाज़ार के वेबपोर्टल, जिसे स्पाइसेस बोर्ड और मेइटी(MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया था, में शामिल किया जाएगा।

यह परियोजना, मसाला प्रसंस्करण की दक्षता सुनिश्चित करने तथा खेत से लेकर खाने के मेज़ तक के स्तर पर अनुमार्गणीयता लाने और इ-स्पाइस बाज़ार के वेबपोर्टल के ज़रिए व्यापार केलिए कृषकों, व्यापारियों, निर्यातकों तथा मसाला आपूर्ति शृंखला के अन्य पणधारियों को प्रत्साहन देने में सहायक होगी।

ग) मानक व व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ़)

स्पाइसेस बोर्ड, विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (एफ़एओ) अधीन मानक व व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) के सहयोग के साथ "भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार" शीर्षक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। परियोजना का कार्यकाल तीन वर्ष है।

परियोजना का लक्ष्य भारत से विदेशी बाज़ारों केलिए सुरक्शित व उच्च-गुणवत्तायुक्त मसालों का निर्यात बढ़ाना है। परियोजना, चार मसालों, अर्थात; जीरा, सौंफ (गुजरात और राजस्थान), धनिया (मध्य प्रदेश) और काली मिर्च (आंध्र प्रदेश), को लक्षित करती है । जिलों का चयन, उत्पादन के आंकड़ों, इन क्षेत्रों में किसानों के रवैये और रुचि और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सलाह के आधार पर किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए खेती, उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रथाओं के मानकों को बढ़ाना है और इस प्रकार छोटे पैमाने के किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं और अन्य सीमांत (आदिवासी) समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करना है, और गरीबी कम करने के प्रयासों का समर्थन करना है।

यह परियोजना, एसटीडीएफ़, एफ़एओ तथा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है। एफ़एओ, अंतर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन साझेदार है। भारत में अपने देशी कार्यालय के ज़रिए एफ़एओ, एशिया व पसफिक प्रादेशिक कार्यालय इसके कार्यान्वयब केलिए उत्तरदाई है। स्पाइसेस बोर्ड, इस परियोजना के स्थानीय साझेदार है और सभी स्थानीय क्रिया-कलापों तथा उनके समायोजन सुनिश्चित करेगा।
इस परियोजना से 1200 छोटे जोत वाले किसानों, जो अपनी आय का एकमात्र स्रोत खेती पर निर्भर हैं, को सीधे लाभ होने की उम्मीद है। परियोजना का उद्देश्य, चार चयनित मसालों में चुनौतियों का समाधान करना है ताकि गरीब, ग्रामीण परिवारों को खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करने और व्यापार के अवसरों से लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके। यह भारत और निर्यात बाजारों में बेहतर खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य में भी योगदान देगा। परियोजना को एक सहयोगी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि विकसित मसाला प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना की समाप्ति के बाद निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत के अन्य हिस्सों में बढ़ाया जाएगा।

लक्षित परियोजना में चयनित किसानों का बेसलाइन सर्वेक्षण प्रगति पर है और फसल विशेष जीएपी और जीएचपी की समीक्षा की जा रही है। जीएपी और जीएचपी को अंतिम रूप देने पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रशिक्षक लक्षित गांवों में मसाला किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और किसानों को अपने खेतों में जीएपी और जीएचपी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

परियोजना के अंत में, यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना के तहत विचार किए जा रहे क्षेत्रों ने विशेष मसालों के संबंध में एसपीएस मुद्दों को पूरा करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू किया होगा, इस प्रकार प्रमुख निर्यातकों के साथ संबंधों के माध्यम से नए बाजारों तक पहुंच पैदा होगी। यह भी एक मॉडल बनाने की उम्मीद है जिसे अन्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।

परियोजना के अंत में, यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना के तहत विचार किए जा रहे क्षेत्रों ने विशेष मसालों के संबंध में एसपीएस मुद्दों को पूरा करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू किया होगा, इस प्रकार प्रमुख निर्यातकों के साथ संबंधों के माध्यम से नए बाजारों तक पहुंच पैदा होगी। यह भी एक मॉडल बनाने की उम्मीद है जिसे अन्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।

घ) एईपी के अनुरूप मसालों के निर्यात को दोगुना करना तथा इंडगैप(IndGAP) प्रमाणन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि

स्पाइसेस बोर्ड और भारतीय गुणवत्ता परिषद(क्यूसीआई) ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए "**एईपी के अनुरूप मसालों के निर्यात को दोगुना करना तथा इंडगैप(IndGAP) प्रमाणन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि"** - शीर्षक परियोजना केलिए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

गुणवत्ता आश्वासन, कृषि जैव विविधता, अनुरेखणीयता, जीएपी प्रमाणीकरण, सतत विकास लक्ष्यों का मानचित्रण, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्यात संवर्धन और सतत निर्यात जैसे कई उद्देश्यों के साथ परियोजना की कल्पना की गई है।

परियोजना के तहत शुरू में जिन मसालों पर विचार किया गया हैं, उनमें, वारंगल में मिर्च, राजस्थान के दो जिलों में जीरा- बाड़मेर और जालोर, इडुक्की में इलायची (छोटी), चिकमंगलूर में कालीमिर्च और तेलंगाना के करीमनगर में हल्दी शामिल हैं।